

ज्ञापन

क्रमांक ५२७९ -६०८-१(२) भोपाल, दिनांक २८ मार्च, १९६९

प्रति

शासन के समस्त विभाग,  
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मंत्रालय,  
समस्त संभागीय आयुक्त,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त कलेक्टर,  
मध्य प्रदेश।

विषय:- रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारियों द्वारा गोपनीय रिपोर्ट्स में  
अस्पष्ट एवं अपर्याप्त टिप्पणी का लिखा जाना - आवश्यक  
हिदायतें।

शासन के ध्यान में यह लक्ष्य आया है कि, अधिकारियों के कार्य  
पर गोपनीय रिपोर्ट ठीक तथा उचित ढंग से नहीं लिखी जाती। इसके फलस्वरूप  
रिपोर्ट्स कभी कभी अस्पष्ट तो होती ही हैं, साथ ही उनसे संबंधित अधिकारों  
की व्यवसायिक योग्यता, व्यक्तित्व तथा उसके चरित्र का सही मूल्यांकन भी  
संभव नहीं हो पाता। शासन द्वारा इस संबंध में समय समय पर आवश्यक  
हिदायतें जारी भी की गई हैं और साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग  
(संगठन तथा कार्यप्रणाली) के ज्ञापन क्रमांक ६६।२६७-६कारं तथा का० दिनांक  
१२-३-१९६८ के साथ सामान्य पुस्तक परिपत्र, भाग एक क्रमांक ७ वाक्य  
अधिकारियों के संबंध में गोपनीय रिपोर्ट नामक एक पुस्तिका भी सर्व  
संबंधित की जानकारी हेतु प्रसारित की गई है।

२. अक्सर गोपनीय रिपोर्ट में सन्तोषजनक ( Satisfactory )  
औसत ( Average ) तथा औसत से अधिक ( Above average )  
आदि शब्दों का उपयोग किया जाता है, जिनके विभिन्न अर्थ निकाले जा  
सकते हैं, विशेषकर जब अधिकारियों को उच्च पदों के लिए चयन करना  
होता है। अतः आवश्यक यह होगा कि उपरोक्त शब्दों का प्रयोग न किया  
जाए बल्कि रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारी के लिये आवश्यक है कि वह  
अधिकारियों का क्रमशः अल्प ( Poor ), पर्याप्त ( Fair )  
अच्छा ( Good ), बहुत अच्छा ( Very good ) तथा उत्कृष्ट  
( Outstanding ) श्रेणियों के अनुसार मूल्यांकन करें। साथ ही

को टिप्पणी नहीं (Nothing comment) ) अधवा कुछ नहीं

2

कोडना ( Nothing to add ) आदि शब्दों का भी प्रयोग  
नहीं किया जाय। उच्च न्यायालय अधिकारी द्वारा, जिसे अधिकारी पर  
रिपोर्ट लिखी है उसका कार्य नहीं देना गया है, तो उसे इस  
बात का उल्लेख करना चाहिए। अगर पुनर्विलोकन अधिकारी यह महसूस

करता है कि रिपोर्ट लिखी जानेवाले अधिकारी को रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारी  
द्वारा अधि-मल्यांकित (Over-rated ) अधवा अधो-मल्यांकित  
(Under-rated ) किया गया है, तो संबंधित रिपोर्ट को समर्थित (Endorsing ) करते समय उसे तथ्य का, औचित्य सहित उल्लेख करना

निवेदन है कि भविष्य में ऊपर केडिक्टा २ में दी गई हिदायतों  
को वास्तविक गोपनीय रिपोर्ट लिखते समय ध्यान में रखा जाय।

( म० प्र० श्री वारदाव )  
मुख्य सचिव,  
मध्य प्रदेश शासन

क्रमांक ५२८० -६०८-२(२) भोपाल, दिनांक २८ मार्च, १९६६

प्रतिलिपि :-

१. निवन्धक, उच्च न्यायालय, म० प्र०, जबलपुर,  
सचिव, लोक सेवा आयोग, म० प्र०, इन्डौर
२. राज्यपाल के सचिव, सैनिक सचिव,  
सचिव, राज्य सतर्कता आयोग, म० प्र०, भोपाल,  
सचिव, विधान सभा सचिवालय, म० प्र०, भोपाल,
३. मुख्य मंत्रियों के निजी सचिव,  
राज्य मंत्रियों के निजी सहायक
४. स्थापना अधिकारी। शिक्षा अधिकारी। अभिलेख अधिकारी। पंजीयक,  
म० प्र० सचिवालय,
५. महालेखापाल, म० प्र०, ग्वालियर,  
को सूचनाधी अधिषिक्त।

20/3/66

मुख्य सचिव ।

संख्या ६-३-६६